12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation Arising out of Demands of School Teachers in U. P.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : I call the attention of the Minister of Education to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon, namely :—

> "The situation arising out of the demands of teachers of higher secondary schools in U.P. resulting in closure of the schools."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : The U. P. Madhyamik Shikshak Sangh, which is an association of teachers of aided higher secondary schools in the State, have pressed the State Government to accept the following demands :—

(i) Payment of arrears of salaries of the school teachers

(ii) Salaries of teachers in aided schools to be disbursed from the State Treasury

(iii) Parity in the pay-scales and dearness allowance to teachers and ministerial staff of aided schools and Government institutions

(iv) Implementation of pay scales recommended by Kothari Commission; and

(v) Sanction of C.T. grade to JTC and BTC teachers.

Some complaints have, no doubt been received about delay in payment of salaries of teachers by the managements of private institutions. The District Education authorities in the State have instruction to attend to any such case most promptly and to pay the salaries directly to the teachers after deducting the amount from the maintenance grant, if necessary.

On administrative and financial grounds, the State Government is not in a position to accept the demands that the salaries of non-Government teachers should be paid through the Government Treasury.

As regards parity in salary scales and dearness allowance, continuous efforts have been made since 1947 to increase the emoluments of teachers in aided schools and to bring them nearer those working in Government schools. In view of the disparity in the service and other conditions of the employees of aided schools as also the inadequacy of resources, it has not yet been possible to establish complete parity. In view of financial stringency, it has not been possible for the State Government to fully implement the recommendations of Kothari Commissions regarding the pay-scales of either the Government or the aided school teachers as also the sanction of C.T. grade automatically to J.T.C. and B.T.C. teachers.

A deputation of the Madhyamik Shikshak Sangh waited on the Governor of U.P. on October 29, 1968 to press their demands. Although the position was fully explained to them, the Sangh did not feel satisfied and they served a notice on the State Government indicating that the Secondary school teachers will go on an indefinite strike from December 2, 68 for the fulfilment of their demands.

Apprehending that the strike will effect the studies of the students whose examinations were coming near the State Government prohibited strikes from November 27, 1968 by issuing an order under the U. P. Essential Services Maintenance Act, 1966. The order is to be operative for 6 months and is to cover all services under recognised educational institutions in U.P. and universities incorporated by or under an U.P. Act.

The secondary school teachers launched the agitation on Novemher 25, 1968 by picketing the gates of the Council House, Lucknow thereby preventing the Government servants from entering the Council House. When all attempts to persuade them to permit the Secretariat employees to attend their offices failed the police had to be called. When further persuation also failed, the teachers were taken away from the scene and all, except a few, released. Next day, the teachers came again to the Secretariat in groups and the events of the earlier day were repeated. Till yesterday evening 643 secondary school teachers and 21 students were arrested for preventing Government servants going to duty.

As a result of State-wide strike by the aided secondary school teachers, institutions in 14 districts were closed by the District Magistrates. Institutions in 12 districts remained closed on 2nd and 3rd December, 1968 on account of the regional rallies. In other 28 districts, about half the institutions were affected because of strike.

In a telephone message received just now, the State Government has said that in response to the Governor's appeal on the A.I.R. last night the President of the Sangh has offered to sit in a round table with Government representatives to discuss the matter and resolve it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : What is he going to do ?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : 1,000 men have been put behind bars.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में जो स्कूल हैं वे गैर-सरकारी स्कूल हैं और वे सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों से चलते हैं ? क्या यह भी सही है कि बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है, उसमें से उन लोगों ने, वैसे स्कूलों ने बहुत सहायता दी है ? क्या यह भी सही है कि अगर वे ऐसा न करते तो सरकार को स्वयं अपने स्कूल खोलने पड़ते ? ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि इन दोनों प्रकार के स्कूलों में इतना फर्क हो, जो सरकारी शिक्षक हैं और जो गैर सरकारी शिक्षक हैं उनकी तनख्वाहों में इतना अधिक अन्तर हो ?

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में जो वेतन शिक्षकों को मिलते हैं उनसे कहीं कम वेतन वहां के शिक्षकों को मिलते हैं ? इसके विरुद्ध क्या यह सही है कि उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है ? पिछले साल मैंने ऐसा सुना था कि उनको बीस रुपया ऐड हाक अनुदान के रूप में मिला था इसी बात पर कि वहाँ वेतन बहुत कम मिलते हैं । क्या यह सही है ? क्या यह आप समझते हैं कि उनके ग्रेड आफ पे में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिये, उनकी तनख्वाह ऊपर जानी चाहिये चूंकि वहां के शिक्षकों को चपड़ासियों से भी कम तनख्वाह मिलती है ?

बहुत दिनों से हम यह सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी है। परन्तु जो शिक्षक हैं और जितना महत्वपूर्ण काम वे कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके अच्छे गार्डियनशिप के बिना अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में बढ़ती जा रही है क्या सरकार जिस का शासन अभी उत्तर प्रदेश में है यह समझती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को मदद प्रदान की जाए, उसको अनुदान दे कर शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए ? मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि अध्यापक संघ के जो नेता हैं वे सरकार से मिल कर बात करने वाले हैं। परन्तु बात करने में जो बुनियादी बात है उस पर सरकार अगर गौर नहीं करती है, अगर सरकार यह कहती है कि अभी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अभी वह कुछ फैसला नहीं कर सकती है तो यह कोई तर्कसंगत बात नहीं हैं। अभी सरकार इस पर गौर करे कि हां उनके साथ ज्यादती हो रही है और आगे इसका कोई उपाय करे। अगर उनको इस बात का विश्वास सरकार दिलाये कि उनकी मांगें सही हैं, जायज हैं तो फिर उसके बाद आगे चल कर बातचीत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करने वाली है, यह मैं जानना चाहती हूं।

कोठारी कमिशन बहाल करने से पहले सरकार को सोचना चाहिये था कि खर्चा बढ़ेगा। कोठारी कमिशन के जो सुझाव आए हैं उनको क्या सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक देने का विचार कर रही है। जो इन सुझावों को अंगीकार नहीं करेंगे सरकार क्या उनके ऊपर कोई कारंवाई नहीं करेगी और कोठारी कमिशन की रिपोर्ट को भी और सब रिपोर्टों की तरह से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा ?

श्री भागवत झा आजाद : यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी स्कूल बहुत अधिक हैं। यह भी सही है कि गैर-सरकारी और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में बहुत फर्क है। यह बात भी सही है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों की तुलना में शिक्षकों को कम वेतन मिलता है। अभी जो हमको सूचना मिली है, उसके अनुसार ये शिक्षक सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और वहां पर इस प्रश्न का कोई हल निकालेंगे। यह भी सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि कोठारी कमिशन के स्कैल्ज को, वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार यह अनुदान क्यों नहीं देती है। यह प्रश्न सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों का है और केन्द्रीय सरकार ने सब राज्यों पर यह प्रभाव डाला है कि कोठारी कमीशन के वेतनमानों का कार्यान्वियन किया जाये। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश की कठिनाई यह है कि वहां पर सब से अधिक स्कूल हैं, सब से अधिक शिक्षक हैं और उस को सब से अधिक पैसा चाहिए। इसलिए जब तक वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है और वह एडीशनल रीसोर्सिज की व्यवस्था नहीं करती है, तब तक इस बारे में कुछ करना सम्भव नहीं है।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : अभी मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है, उस से कोई रास्ता नहीं निकला है। इस सरकार की यह नीति है कि जब झगड़ा हो जाता है, तब वह बातचीत करना शुरू करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जो बातचीत हो रही है, वह पहले क्यों नही हुई। मुझे यह भी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रैजिडेंट, श्री कमलापति त्रिपाठी, प्रधान मन्त्री से मिले थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि शिक्षकों की मांगें पूरी की जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार अपने पास से रुपया दे कर शिक्षकों को कम से कम वे सुविधायें प्रदान करने के लिए तैयार है, जो संविद सरकार ने अपने जमाने में देने का आश्वासन दिया था।

श्री भागवत झा आजाद : यह बात नहीं है कि बातचीत अभी ही हुई। बातचीत पहले भी हुई थी और जिन बातों का मैंने अभी हवाला दिया है, वे शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को पहले भी कही गई थीं। पिछली रात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आकाशवाणी से अपना वक्तव्य प्रसारित किया। उसके बाद शिक्षकों ने कहा कि वे उनसे मिलना चाहेंगे। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रश्न है, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि केवल राज्य सरकारें ही सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही राज्य सरकार नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की अन्य राज्य सरकारें ही—प्राइमरी, मिडल या हायर सैकंडरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों को कार्यान्वित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्राईमरी स्कूलों के शिक्षक एक लाख हैं। अगर उन्हें 150 रुपये का न्यूनतम वेतन दिया जाये, तो उसके लिए सात करोड़ रुपये चाहियें। जब तक वहां की चुनी हुई सरकार अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था नहीं करती है, तब तक हमारे लिए कुछ देना सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में परिस्थिति की गम्भीरता को नहीं आंक रही है। अभी तक तो ऐसा होता रहा है कि अगर कहीं पर छात्रों में आन्दोलन होता था, तो वहाँ के अध्यापक शान्त रहते थे और अगर अध्यापक कोई आन्दोलन करते थे, तो छात्र शान्त रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय उत्तर प्रदेश में अध्यापक और छात्र दोनों आन्दोलन कर रहे हैं, जो कभी भी एक विषम रूप धारण कर सकता है। केन्द्रीय सरकार ने परिस्थिति की गम्भीरता को इस दृष्टि से नहीं देखा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

छोट. छोटी बातों पर आर्डिनेंस लागू करने का परिणाम यह होगा कि आर्डिनेंस का महत्व ही समाप्त हो जायेगा। जब सरकार के पास और साधन तथा अधिकार उपलब्ध हैं, तो आर्डिनेंस लागू कर के उस की धज्जियां उड़ाने की परंपरा इस देश में नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि आगे चल कर कई और गम्भीर विषयों के बारे में आर्डिनेंस लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मुझे यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ विषयों में केन्द्रीय सरकार को अन्धेरे में रखे हुए है। अभी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है चूंकि हमारे पास साधनों का अभाव है, इस लिए हम गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के वेतनमानों को समान नहीं कर सकते हैं। मेरे हाथ में श्री राजेन्द्र वर्मा, उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा 15 नवम्बर, 1967 को जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि है, जिस में से कुछ शब्द मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ: "इस मांग के सभी पक्षों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आज्ञा प्रदान की है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को 1 अगस्त, 1967 से उसी दर से महंगाई भत्ता दिया जाये, जिस दर से उसी स्तर के राजकीय शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।" एक ओर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की यह मांग है कि गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को राजकीय शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के समान वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाये और प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे में आदेश भी जारी हो चुका है और दूसरी ओर मंत्री महोदय कहते हैं कि साधनों के अभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है। इस का अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को पूरी सूचना नहीं दे रही है।

शिक्षकों की पहली मांग यह है कि उन्हें पिछला वेतन दिया जाये और इस के साथ ही साथ उन्हें वेतन सरकारी खजाने से दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आप को यह सुन कर कष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश में, जहां सब से कम वेतन हैं, निजी विद्यालयों में अध्यापकों से हस्ताक्षर तो 120 रुपये और 150 रुपये के करा लिये जाते हैं और वास्तव में उन्हें केवल 100 रुपये दिये जाते हैं। इसके बावजूद वे लोग अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण मन मार कर भी काम कर रहे हैं। संविद सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि अध्यापकों को सीधे राजकीय कोष से वेतन दिया जायेगा मैनेजमेंट की ओर से वेतन-वितरण नहीं किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस निर्णय को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में हायर सेकंडरी स्कूल के प्रिंसीपल का न्यूनतम वेतन 343 रुपये और अधिकतम वेतन 718 रुपये है, जबकि हरियाणा में वे वेतन क्रमशः 800 रुपये और 1200 रुपये हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रेन्ड टीचर का न्यूनतम वेतन 182 रुपये और अधिकतम वेतन 393 रुपये हैं, जबकि हरियाणा में वे वेतन क्रमशः 515 रुपये और 618 रुपये हैं। अध्यापकों के वेतनों के सम्बन्ध में आज देश में यह विषमता चल रही है। कोठारी कमीशन अपना प्रतिवेदन दे चुका है। इस स्थिति में सरकार उत्तर प्रदेश के साथ यह बेइन्साफ़ी कब तक जारी रखना चाहती है? परसों मैंने एक नारा सुना कि "जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है।" आज अध्यापकों में जो असन्तोष है, इस नारे से उसकी एक झलक मिलती है और हमें इस को बड़ी गम्भीरता से देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री भागवत झा आज़ाद और डा० त्रिगुण सेन, जो स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं, देश के सब से बड़े और शिक्षा में सब से पिछड़े हुए राज्य के सम्बन्ध में ऐसा निर्देश देंगे, जिस से यह आन्दोलन, जो एक भयंकर रूप लेता जा रहा है, किसी प्रकार शान्त हो सके।

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN): I think all his questions have been replied by my colleague, Mr. Bhagwant Jha Azad. I do agree

[Dr. Triguna Sen]

that the salary scales of U. P. teachers are the lowest in the whole of the country. Their demand is that the scale of primary school teachers should be raised. Their second demand is that they do not get their salary even after one year. Their third demand is that on 1.8.67 they were given the dearness allowance increase as other officials, but when it has been subsequently raised, they were denied the increase.

I have been inclined to support their demands. At our request, the pay scale of the primary teachers of U. P. who were getting only Rs. 100 as their minimum salary has been increased in last September to Rs. 110. That too is insufficient. That is what I feel. There must be some machinery to see that the teachers get their pay every month. But, unfortunately, I am told that the management pay their salary after one year. Something should be done to see that this paltry salary is given on the first day of every month. I do agree that the dearness allowance increase has been given on 1.8.67. Since this dearness allowance has been raised, that also should be given to the teachers. I am always in contact with the Governor of U.P. By raising from Rs. 100 to 110, they say they have to incur an additional expenditure of about Rs. 3 crores. If they want to raise it further, naturally they want more money. But I am trying to find a way out and I hope something will be done about it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : These are pious wishes.

DR. TRIGUNA SEN : I do not want to express any pious wish. But I can only say that we are trying our best. But at the same time, I must say that the path they have chosen to realise their demands by going on a strike is not a correct one. I met the representatives of the primary teachers as also of tho secondary teachers. I appeal to them 'You are to mould the character of the students and if you go on strike, it is setting a very dangerous example before the students'. They know what we are doing. We discussed with them.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What is the other way out ?

DR. TRIGUNA SEN : We are at it, and I do hope that we will be able to do something in this regard.

SHRI S. M. BANERJEE : Today, when the hon. Minister of Education is answering this Call Attention Notice, in my State, more than a thousand teachers who are supposed to be the builders of the nation, and students, are behind the bars. They should have been released when they have now agreed that we should have a discussion with the Governor.

Now, what is the pay of the teacher today ? Whereas in the Government, a peon gets Rs 105, a trained under-graduate teacher gets Rs. 104, and an untrained under-graduate teacher gets Rs. 84 only. The Kothari Commission has recommended a national minimum wage-scale for teachers. The other day, the Education Minister in the other House stated that it has been implemented by the Haryana, Punjab and Bihar Governments. In both the States, whether it is Bihar or Punjab, there is now the President's rule, and unfortunately in Uttar Pradesh also, there is President's rule, and I want the Minister to intervene in the matter ; the Governor should intervene in the matter.

Now, the Minister has said that the teachers have chosen the wrong way. I shall read from a memorandum submitted to us by Shri Harihar Pandey, convener of the action committee of the Uttar Pradesh Madhyamik Shikshah Sangh, in which it has been said :

> "The U.P. Madhyamik Shikshah Sangh has tried all possible means of a negotiated settlement of our aforesaid demands. We wrote letters, presented a memorandum, met in deputation, and staged mass demonstration to prove our demands but could not elicit any assurance from the Government. We rather received a treatment of indifferance. The Government has thus exhausted our patience and in a way forced this movement upon us, but now since we have come out, we have resolved to fight it to the last in spite of all provocations, and harassments inside and outside the jail, and actual and threatened repressive measures."

It was known to the Governor that the teachers wanted parity in DA and they simply wanted the implementation of the Kothari Commission's recommendations. They wanted that the concession granted during the SVD government should not be withdrawn. With your permission, I will send the document to you ; it will show that the concession which was given by the SVD government has been withdrawn. But the Governor has chosen to prohibit the strike instead of solving this problem, and our brave teachers are going ahead and courting arrest, and even the oldest teachers are courting arrest.

Now the Minister has said that the teachers have chosen the wrong path and they should not have done so. I would only request him to kindly intervene in the matter of release of the teachers so that a favourable condition may be created for a peaceful, negotiated settlement. If he supports the demands of the teachers and if he feels that they are legitimate and justifisd, and if it is not possible for the Governor or for the Government to concede them, I would appeal to him to resign his seat and lead the teachers' movement as a teacher.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, my question is whether, in view of these negotiations, he would see that all the teachers are released so that a favourable condition may be created and whether the Centre will intervene in the matter financially, physically, mentally and morally.

MR. SPEAKER : So, you do not want him to resign ; you withdraw that request then.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : As I have stated, according to a telephonic message just now received, on the appeal by the Governor, the teachers have agreed to sit round the table and resolve the issue. We would request the State Government to create a good climate around the table by telephone.

SHRI S. M. BANERJEE : They should release all the teachers. (*Interruption*) The Home Minister should reply whether he is going to release the teachers.

SHRI SHEO NARAIN *rose*—

MR. SPEAKER : Order, order. I am on my legs. Your name is not there. Otherwise, I would have allowed you also to shout. What do I lose ? (*Interruption*)

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Ask the Minister to release the teachers.

———

12.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

U.P. Krishi Utpadan Mandi (Second Amendment) Niyamavali, West Bengal Markets Regulation Act, etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Second Amendment) Niyamavali, 1968, (Hindi and English versions) published in Notification No. H-5199/XIIB-1314-68 in Uttar Pradesh Gazette dated the 4th November, 1968, under sub-section (3) of section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, read with clause (e) (iv) of the Proclamation dated the 25th February, 1968, as varied by Proclamation dated the 15th April, 1968, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh. [*Placed in Library. See* No. LT-2523/68.]

(2) A copy of the West Bengal Markets Regulation Act, 1968, (President's Act No. 28 of 1968) published in Gazette of India dated the 1st November, 1968, under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968. [*Placed in Library. See* No. LT-2512/68.]